भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या5095
जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।
12चैत्र, 1947 (शक)

प्रगति मंच की प्रभावशीलता

5095. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकास परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के लिए 'प्रगति'एक प्रभावी मंच है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन और परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'प्रगति'मंच सरकारी योजनाओं की निगरानी में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह मंत्रालयों/विभागों में जवाबदेही को किस प्रकार बढ़ावा देता है;

(ग) क्या 'प्रगति'ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार किया है और यदि हां, तो संवर्धित संचार और परियोजना निष्पादन के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 'प्रगति'ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को कम करने में योगदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में किस प्रकार तेजी आई है; और

(ड.) क्या 'प्रगति'के प्रौद्योगिकी के उपयोग ने बेहतर शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण को सुगम बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ड.):** प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइम्ली इम्प्लीमेंटेशन) एक आईटी आधारित बहुउद्देश्यीय और बहु-मॉडल इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों, क्षेत्रीय शिकायतों और परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन और वांछित परिणामों के लिए समीक्षा करना है।

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों जैसे हितधारकों कोअन्य क्षेत्रों के साथ-साथ परियोजनाओं/कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति, शिकायतों के समाधान आदि के संदर्भ में इनपुट प्रदान करने के लिए प्रगति पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया गया है। अब तक 19.12 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 363 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है।

प्रगति की बैठक में लंबित मुद्दों पर चर्चा के मामले में, केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मुद्दों के समाधान के लिए समयसीमा प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे मुद्दों का शीघ्र समाधान करने और परियोजनाएं समय पर पूरी करने में सहायक होता है।हाल ही में एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में स्पष्ट रूप से कहा गया है किप्रगति की समीक्षा अंतर-सरकारी मुद्दोंको हल करने में सहायक रही है। ये समीक्षा खुले संवाद और समस्याओं के सहयोगात्मक समाधान के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, जिससे आपसी समझ बढ़ती है और सहयोगात्मक आयोजना को बढ़ावा मिलता है। एकता और साझा जिम्मेदारी कीभावना को बढ़ावा देकर, प्रगति नेसरकार के विभिन्न स्तरों के बीच की खाई को पाटने में मदद की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नीतियों और परियोजनाओं का कार्यान्वयन अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सुचारू रूप से किया जाए। इसने न केवल शासन की दक्षता में वृद्धि की है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशासन के समग्र ढांचे को भी मजबूत किया है।

*****